



## सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लोन 'राइट-ऑफ' और NPA

### प्रलम्ब के लिये:

[ऋण वसूली न्यायाधिकरण \(DRTs\)](#), [NPA](#), [नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड \(NARC\)](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#), [भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड](#), [SARFAESI अधिनियम](#), [दवाला और शोधन अक्षमता संहिता \(IBC\)](#)

### मेन्स के लिये:

ऋण माफी: नहितार्थ, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता, एनपीए की चुनौतियाँ, एनपीए समाधान के प्रावधान

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

पछिले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा बड़े पैमाने पर **राइट-ऑफ (ऋण माफ करना)** गैर-नष्टिपादति परसिंपत्तियों (**NPA**) में उल्लेखनीय कमी आई है।

- परिणामस्वरूप, बैंकों ने मार्च, 2024 तक अग्रमियों के 2.8% का **NPA अनुपात 12 वर्षों के नमिनतम स्तर पर प्राप्त** कर लिया है।

### बैंकों द्वारा लोन राइट-ऑफ के संबंध में मुख्य आँकड़े क्या हैं?

- लोन राइट-ऑफ:**
  - वर्ष 2015 और वर्ष 2024 के बीच, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने **12.3 लाख करोड़ रुपए** के ऋण माफ किये, जिसमें **पछिले 5 वर्षों** (वर्ष 2020-2024) में ही **9.9 लाख करोड़ रुपए** शामिल हैं।
  - वर्ष 2015 में शुरू किया गया 'एसेट क्वालिटी रिव्यु' के बाद, वर्ष 2019 में ऋण राइट-ऑफ करने का उच्चतम आँकड़ा 2.4 लाख करोड़ रुपए रहा।
  - हालाँकि, तब से **राइट-ऑफ** में कमी आई है, वर्ष 2024 में यह सबसे कम 1.7 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो कुल बैंक ऋण का **सर्फ 1%** है।

//

# LOAN WRITE-OFFS BY BANKS (₹ cr)

Year	Amount
2023-24	1,70,270
2022-23	2,08,037
2021-22	1,74,966
2020-21	2,02,781
2019-20	2,34,170

Source: RBI



- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हिसा:
  - पछिले 5 वर्षों (वर्ष 2020-2024) में कुल ऋण माफी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का हिसा 53% (6.5 लाख करोड़ रुपए) था।
- वसूली दरें:
  - ऋण माफ करने (राइट-ऑफ) के बावजूद, इन ऋणों से वसूली अपेक्षाकृत कम रही है, जो पछिले 5 वर्षों (वर्ष 2020-2024) में केवल 18.7% (1.85 लाख करोड़ रुपए) रही है।
    - वर्ष 2020-2024 के बीच राइट-ऑफ की गई राशि का 81% से अधिक (8 लाख करोड़ रुपए से अधिक) वसूल नहीं हो पाया, जो डिफॉल्ट किये गए ऋणों की वसूली में चुनौतियों को दर्शाता है।
  - ये ऋण खाते अधिकतर वलिफुल डिफॉल्ट थे, जिनमें से कुछ कंपनियों के प्रवर्तक और नदिशक तो देश छोड़कर भाग गए थे।
- NPA अनुपात पर प्रभाव:
  - सितंबर, 2024 तक, PSBs और नज्जी क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का सकल NPA क्रमशः 3.16 लाख करोड़ रुपए और 1.34 लाख करोड़ रुपए था।
  - बकाया ऋणों के प्रतशित के रूप में NPS अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिये 3.01% तथा नज्जी क्षेत्र के बैंकों के लिये 1.86% था।

नोट:

- वलिफुल डिफॉल्टर वह उधारकर्ता या गारंटर होता है, जो 25 लाख रुपए या उससे अधिक की बकाया राशि वाले ऋण को चुकाने में जानबूझकर वफिल रहता है।
- बड़े डिफॉल्टर से तात्पर्य ऐसे उधारकर्ता से है, जिसका ऋण बकाया 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, तथा जिसके खाते को संदिग्ध या घाटे वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- राइट-ऑफ से तात्पर्य किसी गैर-नषिपादति ऋण या परसिंपत्त को बैंक के वत्तीय अभलिखों से हटाने से है, यह मानते हुए कि ऋण की वसूली की संभावना नहीं है।
  - यह प्रक्रिया उधारकर्ता को ऋण चुकाने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करती है, बल्कि वसूली की असंभावना को स्वीकार करती है।

## गैर-नष्पादति परसिंपत्तति(NPA) क्या है?

### परचिय:

- इसका तात्पर्य आमतौर पर एक ऋण या अग्रमि से है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान एक नशिचति अवधि के लिये अतदिय रहता है। ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-नष्पादति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण कभुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये नहीं किया गया हो।
- कृषि के लिये यदि 2 शस्य ऋतुओं/फसली मौसमों के लिये मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### NPA के प्रकार:

- **सकल NPA:** यह अनंतिम राशि में कटौती किये बिना NPA की कुल राशि है।
- **नविल NPA:** सकल NPA में से प्रावधान घटाने पर नविल NPA प्राप्त होता है।
  - प्रावधान का तात्पर्य ऋणों अथवा NPAs से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखे गए धन से है।

### भारत में NPA से नपिटने के प्रावधान:

### बैंड बैंक:

- नेशनल [नेशनल एसेट रकिंसट्रक्शन लिमिटेड \(NARC\)](#) भारत का नामति "बैंड बैंक" है।
  - इन परसिंपत्तियों की बकिरी को सुवधाजनक बनाने के लिये सरकार ने [भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड \(IDRC\)](#) की भी स्थापना की है, जो परसिंपत्तियों को बाज़ार में बेचने का कार्य करती है।
- [वतितीय आसत्तियों के परतभित्किरण और पुनरनरिमाण और परतभित्ति हति का परवरतन अधनियिम \(Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act- SARFAESI अधनियिम\), 2002](#)
- [दवाला और शोधन अकषमता संहति \( Insolvency and Bankruptcy Code- IBC\), 2016](#)
  - इसने इस प्रक्रिया की देखरेख के लिये [राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण \(NCLT\)](#) और [दवाला और शोधन अकषमता संहति \(IBC\)](#) की भी स्थापना की।
- [बैंकों और वतितीय संस्थाओं को शोधय ऋण वसूली अधनियिम \(RDB अधनियिम\), 1993](#)।

## EASE फ्रेमवर्क

- सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वतितीय स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 2018 में [उन्नत पहुँच और सेवा उत्कृषटता \(EASE\) ढाँचा](#) पेश किया है।
- यह शासन, वविकपूरण ऋण, जोखमि प्रबंधन, प्रौद्योगिकी अपनाने और परणामोन्मुखी मानव संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रति करता है, जो कठिभरते बैंकगि परदृश्य के साथ संरेखति वृद्धशील सुधारों को संस्थागत बनाता है, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दकषता और स्थरिता को बढ़ाता है।

## Prudential Lending:

❖ PSBs are now systematically monitoring adherence to risk-based pricing and have established data-driven risk-scoring mechanisms for the appraisal of high-value loans, factoring in group entities.

## IT-based Early Warning Systems:

These systems leverage third-party data to enable timely, proactive action in stressed accounts.

## Stressed Assets Management Verticals:

❖ Dedicated units have been set up for focused slippage prevention and recovery in large-value stressed loans, resulting in a sharp decline in such loans.

## Tech-Enabled Smart Banking:

❖ The adoption of retail and MSME loan management systems has reduced loan turnaround times. Additionally, platforms like OTS (One-Time Settlement) and the e-Bkay stressed assets auction platform have enhanced recovery processes.

## बैंकों द्वारा ऋण माफी क्या है?

### ■ परिचय:

- लोन राइट ऑफ को खाते में डालने, बैंक के परसिंपत्तरिकॉर्ड से लोन को हटाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो यह दर्शाता है कि बैंक को अब राशि वसूलने की उम्मीद नहीं है।
- यह मुख्य रूप से बैंकों द्वारा अपनी बैलेंस शीट को NPA से मुक्त करने तथा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये किया जाने वाला एक लेखांकन उपाय है।
- यह प्रक्रिया बैंकों को वसूली योग्य परसिंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कर देनदारियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की अनुमति देती है।

### ■ लेखांकन तंत्र:

#### ○ NPA वर्गीकरण और प्रावधान:

- भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के वविकपूरण मानदंडों के अनुसार, बैंकों को NPA के लिये प्रावधान बनाना चाहिये, जो परसिंपत्ती की आयु बढ़ने के साथ बढ़ता है और संपार्श्विक के प्राप्त योग्य मूल्य से प्रभावित होता है।
- इससे गैर-नषिपादति ऋणों से संबंधित वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिये सतर्क लेखांकन दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

#### ○ तकनीकी अपलेखन:

- तकनीकी राइट ऑफ को खाते में डालने की प्रक्रिया तब होती है, जब प्रावधान अधिशेष ऋण राशि से मेल खाते हैं, जिससे बैंकों को अपने बैलेंस शीट से ऋण को हटाने की अनुमति मिलती है, जबकि इसे "एडवांस अंडर कलेक्शन" के अंतर्गत ऑफ-बैलेंस शीट आइटम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- राइट ऑफ खाते में डाले जाने के बावजूद, ऋणकर्त्ता की देनदारी बनी रहती है, तथा वधिक और संस्थागत तंत्र के माध्यम से वसूली के प्रयास जारी रहते हैं।

## ■ नयामक दशानरिदेश:

- इसके लिये आवश्यक है कि राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि बैलेंस शीट प्रबंधन और कर दक्षता पर केंद्रित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप हो।
- बैंकों को राइट ऑफ खाते में डाले गए खातों पर नज़र रखना जारी रखना चाहिये तथा रटिर्न को अनुकूलतम बनाने के लिये वसूली के लिये सक्रिय प्रयास करना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि पर कटौती की अनुमति देता है, जिससे बैंकों पर कर का बोझ कम करने में सहायता मिलती है।

## भारत में बढ़ते NPA के कारण क्या हैं?

- **दोषपूर्ण ऋण प्रक्रिया:** ऋणकर्त्ता के चयन के दौरान अपर्याप्त सावधानी और क्रेडिट प्रोफाइल की आवश्यक समीक्षा के परिणामस्वरूप पुनर्भुगतान क्षमताओं का अनुचित मूल्यांकन होता है।
  - इसके अतिरिक्त अंतिम उपयोग निगरानी प्रणालियों की कमी से धन को गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिये मोड़ दिया जाता है, जिससे NPA की समस्या और बढ़ जाती है।
- **वलिफुल डिफॉल्ट और खराब क्रेडिट कल्चर:** वलिफुल डिफॉल्ट की संख्या में वृद्धि, NPA में वृद्धि में योगदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.5 मिलियन रुपए और उससे अधिक के अधिशेष ऋण वाले वलिफुल डिफॉल्टर्स की संख्या में नरिंतर वृद्धि देखी गई है, जो जून 2019 में 10,209 से बढ़कर मार्च 2023 तक 14,159 हो गई है।
  - बार-बार ऋण माफी, विशेषकर कृषि ऋण के लिये, ने ऋण संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
  - ऋण माफी के वादे, भविष्य में ऋण माफी की प्रत्याशा में ऋण न चुकाने के लिये ऋणकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करते हैं।
- **औद्योगिक रुग्णता:** औद्योगिक रुग्णता अपरभावी प्रबंधन, अपर्याप्त तकनीकी प्रगति, तथा सरकारी नीतियों में नरिंतर बदलावों के कारण उत्पन्न होती है, जिससे उद्योग वित्तीय रूप से असंथर हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की ऋण वसूली दर खराब हो जाती है।
- **धोखाधड़ी और कदाचार:** बैंकों और ऋणकर्त्ताओं दोनों द्वारा धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों ने NPA संकट को बढ़ा दिया है।
  - वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारतीय बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों में 166% की वृद्धि हुई और यह संख्या 36,000 से अधिक हो गई।
  - नीरव मोदी-PNB धोखाधड़ी और वजिय माल्या-कगिफशिर डिफॉल्ट जैसे हाई-प्रोफाइल घोटालों ने जनता के विश्वास और वित्तीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
- **वनियामक और नीतगत जोखिम:** RBI के दशानरिदेशों का पालन न करने, जैसे कि वैधानिक और वनियामक पालन में कमियों, के कारण बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, जैसे कि सितंबर 2024 में RBI द्वारा एक्ससि बैंक और HDFC बैंक पर हाल ही में 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
  - इसके अतिरिक्त ऋणों को सदाबहार बनाए रखना और बैलेंस शीट की वडि ड्रेसिंग (स्वस्थ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिये वित्तीय विवरणों में हेरफेर करना) जैसी प्रथाएँ, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी बैंकों के बीच प्रचलित रही हैं।
  - ये प्रथाएँ वास्तविक परसिंपत्त गुणवत्ता को विकृत करती हैं, अंतरनिहित वित्तीय तनाव को छुपाती हैं और सटीक जोखिम आकलन में बाधा डालती हैं।
- **क्षेत्र-वशिष्ट चुनौतियाँ:** वमिानन क्षेत्र में उच्च परचालन लागत जैसे उद्योग-वशिष्ट कारक उच्च NPA का कारण बनते हैं।
  - भारतीय एयरलाइनों को वित्त वर्ष 2025 में 2,000-3,000 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा होने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण उच्च परचालन व्यय और कम टिकट कीमतें हैं।
  - कृषि और MSME को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) देने में अक्सर पुनर्भुगतान संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र के NPA में वृद्धि होती है।
- **समाधान तंत्र में अकुशलता:** ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRT) के समक्ष मामलों के समाधान में देरी एवं दवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) तथा SARFAESI अधिनियम जैसे वसूली संबंधी कानूनों के शथिल कार्यान्वयन से प्रभावी NPA प्रबंधन में बाधा उत्पन्न हुई है।

## NPA वसूली से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वधिक एवं वनियामक बाधाएँ:** भारत में NPA वसूली में शथिल एवं परंपरागत वधिक फ्रेमवर्क से बाधा आ रही है। IBC और SARFAESI अधिनियम जैसे कानूनों के बावजूद, कॉर्पोरेट दवालयिापन मामलों के समाधान में 400 दिनों से अधिक समय लगता है, जैसा कि भारतीय दवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा बताया गया है।
  - ऋणदाता अक्सर वसूली में देरी करने के क्रम में कानून का सहारा लेते हैं, जिससे स्थिति और भी खराब हो जाती है।
- **उचित परसिंपत्त मूल्यांकन और प्राप्ति:** NPA वसूली में सटीक परसिंपत्त मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। बाज़ार की स्थितियों एवं आर्थिक कारकों के कारण इसका अधिमूल्यन या अवमूल्यन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है।
  - कोलेटरल को नकदी में परिवर्तित करना (वशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान या वशिष्ट बाज़ार स्थितियों में) धीमा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि परसिंपत्तियों का अक्सर उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करना जटिल होता है।
- **उधारकर्त्ताओं का सहयोग:** यह NPA वसूली के लिये महत्वपूर्ण है। कई उधारकर्त्ताओं में या तो चुकाने की क्षमता या इच्छा की कमी होती है, जिसके कारण वे संपत्तियों को छपाने या उसका कम मूल्यांकन करने या कानून का उपयोग कर इसमें देरी करते हैं, जिससे वसूली प्रक्रिया में काफी बाधा आती है।
- **परचालन अक्षमताएँ:** खराब दस्तावेज़ीकरण, अपर्याप्त ट्रैकिंग प्रणाली एवं समन्वय की कमी जैसी आंतरिक अक्षमताओं से NPA वसूली में बाधा आती है।
  - केंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली के अभाव में सूचना के कुप्रबंधन एवं वसूली में देरी होने के साथ लागत में वृद्धि होती है।

